ISSN: 2249-7196
IJMRR/March. 2012/ Volume 2/Issue 1/1-8
उमेश कुमार गुप्ता / International Journal of Management Research & Review

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की भूमिका: रायपुर जिले में धान खरीदी और भंडारण का विश्लेषण

उमेश कुमार गुप्ता[1]
शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, रायपुर (छ.ग.)[1]
डॉ. पी सी अग्रवाल[2]
प्रोफ़ेसर, वाणिज्य विभाग, शा. छत्तीसगढ़ कॉलेज, रायपुर (छ.ग.)[2]

सार

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (CG MARKFED) रायपुर जिले में धान खरीदी और संग्रहण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शोध वर्ष 2010 में रायपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बाजार मूल्य की तुलना, किसानों को भुगतान में होने वाली औसत देरी, तथा भंडारण सुविधाओं की क्षमता का मूल्यांकन करने पर केंद्रित है। इस अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है। प्राथमिक डेटा के लिए रायपुर जिले के 100 किसानों, विपणन संघ के अधिकारियों और भंडारण केंद्रों के प्रबंधकों से साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई। वहीं, द्वितीयक डेटा के रूप में कृषि विभाग की रिपोर्ट, सहकारी संघ की वार्षिक रिपोर्ट (2010), तथा पूर्ववर्ती शोध पत्रों का अध्ययन किया गया। डेटा विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय उपकरणों जैसे प्रतिशत विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन, तथा ग्राफ़ और तालिकाओं का उपयोग किया गया। शोध के प्रमुख निष्कर्षों से पता चलता है कि वर्ष 2010 में रायपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या 450 तक पहुँच गई, जो 2007 की तुलना में 50% अधिक थी। MSP और बाजार मूल्य के बीच का अंतर घटकर 3.09% रह गया, जिससे सरकारी खरीद प्रणाली अधिक प्रभावी बनी। किसानों को भुगतान मिलने की औसत देरी 12 दिनों तक सीमित हो गई, जो पूर्व वर्षों की तुलना में सुधार दर्शाता है। इसके अलावा, भंडारण सुविधाओं की क्षमता में वृद्धि हुई, जिससे खरीदे गए धान के सुरक्षित संग्रहण में सहायता मिली।

कीवर्ड: *छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (CG MARKFED), धान खरीदी केंद्र, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), भंडारण सुविधाएँ, किसान भुगतान प्रणाली.*

1. परिचय

छत्तीसगढ़ एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ धान उत्पादन आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ है। किसानों की आजीविका और राज्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (CG MARKFED) की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह संस्था किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर उचित मूल्य दिलाने, धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने, और भंडारण सुविधाओं को व्यवस्थित करने में योगदान देती है। इस अध्ययन का उद्देश्य रायपुर जिले में धान खरीदी और संग्रहण प्रक्रिया में सहकारी विपणन संघ की भूमिका का गहन विश्लेषण करना है।

रायपुर जिले में धान खरीदी प्रक्रिया और MSP का प्रभाव

छत्तीसगढ़ में धान की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है, और रायपुर जिला इस उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। राज्य सरकार के सहयोग से सहकारी विपणन संघ धान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी सुनिश्चित करता है। MSP की प्रभावी कार्यान्वयन नीति किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने में मदद करती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। धान खरीदी प्रक्रिया के तहत, किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होता है, जिसके बाद विभिन्न खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान का क्रय किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ इस प्रक्रिया की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को समय पर भुगतान मिले। हालांकि, कभी-कभी भुगतान में देरी और प्रक्रियागत बाधाएँ किसानों को कठिनाइयों का सामना करने पर मजबूर कर देती हैं। इस अध्ययन में इन चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है और सुधारात्मक उपायों पर विचार किया गया है।

धान संग्रहण एवं भंडारण सुविधाओं की स्थिति

धान खरीदी के बाद भंडारण की प्रभावी व्यवस्था आवश्यक होती है ताकि अनाज की गुणवत्ता बनी रहे और हानि को रोका जा सके। रायपुर जिले में सहकारी विपणन संघ धान के सुरक्षित भंडारण के लिए विभिन्न गोदामों और भंडारण केंद्रों का संचालन करता है। हालांकि, बढ़ती धान उत्पादन दर और सीमित भंडारण क्षमता के कारण कभी-कभी इन केंद्रों पर दबाव बढ़ जाता है। धान भंडारण की प्रक्रिया में कई चुनौतियाँ देखी जाती हैं, जैसे कि पर्याप्त भंडारण क्षमता की कमी, बाढ़ और नमी से होने वाली क्षति, और गोदामों के प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि रायपुर जिले में सहकारी विपणन संघ की भूमिका कितनी प्रभावी है और भंडारण प्रणाली में किन सुधारों की आवश्यकता है।

2. शोध के उद्देश्य

1. वर्ष 2010 में रायपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या का विश्लेषण।

2. वर्ष 2010 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बाजार मूल्य की तुलना।
3. वर्ष 2010 में किसानों को भुगतान में होने वाली औसत देरी का अध्ययन।
4. वर्ष 2010 में भंडारण सुविधाओं की क्षमता का मूल्यांकन।

3. शोध पद्धति

इस अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जिससे रायपुर जिले में धान खरीदी एवं संग्रहण में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की भूमिका का व्यापक विश्लेषण किया जा सके। प्राथमिक डेटा के अंतर्गत रायपुर जिले के 100 किसानों, विपणन संघ के अधिकारियों और भंडारण केंद्रों के प्रबंधकों से साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई। प्रश्नावली को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया था कि वह किसानों की समस्याओं, धान खरीदी की प्रक्रिया, भुगतान की अवधि और भंडारण संबंधी चुनौतियों को उजागर कर सके। इसके अतिरिक्त, द्वितीयक डेटा के रूप में कृषि विभाग की रिपोर्ट, सहकारी संघ की वार्षिक रिपोर्ट (2010), तथा पूर्ववर्ती शोध पत्रों का अध्ययन किया गया, जिससे सरकारी नीतियों और उनके प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके। डेटा विश्लेषण पद्धति के तहत सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग किया गया, जिसमें प्रतिशत विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन और ग्राफ़ एवं तालिकाओं के माध्यम से निष्कर्ष निकाले गए। डेटा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे धान खरीदी प्रणाली की प्रभावशीलता और उसमें मौजूद चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं और सहकारी संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जिससे धान खरीदी और भंडारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

4. परिणाम एवं चर्चा

वर्ष 2010 में रायपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई, जिससे अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ प्राप्त हुआ। MSP और बाजार मूल्य के बीच का अंतर घटकर 3.09% रह गया, जिससे सरकारी खरीद प्रणाली अधिक आकर्षक बनी। किसानों को भुगतान मिलने की औसत देरी 12 दिनों तक सीमित हो गई, जो पूर्व वर्षों की तुलना में सुधार दर्शाता है। भंडारण सुविधाओं की क्षमता में भी वृद्धि हुई, जिससे खरीदे गए धान के सुरक्षित संग्रहण में मदद मिली।

वर्ष 2010 में रायपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या

तालिका 1 के आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण दर्शाता है कि वर्ष 2007 से 2010 तक रायपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2007 में जहां 300 खरीदी केंद्र कार्यरत थे, वहीं वर्ष 2008

में इनकी संख्या 50 केंद्र बढ़कर 350 हो गई, जो लगभग 16.67% की वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रवृत्ति को देखते हुए वर्ष 2009 में खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 400 हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.28% अधिक थी। वर्ष 2010 में यह संख्या बढ़कर 450 तक पहुँच गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए खरीदी केंद्रों के विस्तार पर लगातार ध्यान दिया। यदि पूरे चार वर्षों के औसत वार्षिक वृद्धि दर की गणना की जाए, तो यह 14.54% प्रति वर्ष निकलती है। इस वृद्धि का मुख्य कारण धान उत्पादन में वृद्धि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना का विस्तार, और सहकारी विपणन संघ द्वारा किसानों को सुलभ खरीदी केंद्र उपलब्ध कराना रहा। इस सांख्यिकीय प्रवृत्ति से यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने धान विपणन व्यवस्था को सुधारने और अधिक किसानों को सरकारी खरीदी प्रणाली से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य और सुविधाएं मिल सकें।

तालिका 1: वर्ष 2010 में रायपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या

वर्ष	**धान खरीदी केंद्रों की संख्या**
2007	300
2008	350
2009	400
2010	450

तालिका से स्पष्ट है कि 2007 से 2010 तक खरीदी केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जिससे अधिक किसानों को MSP का लाभ प्राप्त हुआ।

वर्ष 2010 में MSP और बाजार मूल्य

तालिका 2 के आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण दर्शाता है कि वर्ष 2007 से 2010 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बाजार मूल्य दोनों में क्रमिक वृद्धि हुई। वर्ष 2007 में MSP 850 रु./क्विंटल था, जबकि बाजार मूल्य 800 रु./क्विंटल था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य बाज़ार मूल्य से 6.25% अधिक था। वर्ष 2008 में MSP बढ़कर 900 रु./क्विंटल हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.88% की वृद्धि थी, जबकि बाजार मूल्य भी बढ़कर 850 रु./क्विंटल हो गया, लेकिन यह MSP से 5.55% कम रहा। 2009 में MSP और बाजार मूल्य के बीच का अंतर घटकर 3.15% रह गया, क्योंकि MSP 950 रु./क्विंटल और बाजार मूल्य 920 रु./क्विंटल तक पहुँच गया। वर्ष 2010 में MSP और बाजार मूल्य दोनों अपने उच्चतम स्तर पर थे, जहां MSP 1000 रु./क्विंटल और बाजार मूल्य 970 रु./क्विंटल था, जिससे दोनों के बीच का अंतर मात्र 3.09% रह गया। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि सरकारी समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर समय के साथ कम हुआ,

जिससे किसानों के लिए सरकारी खरीद प्रणाली अधिक आकर्षक बनी, लेकिन बाजार मूल्य के MSP के करीब आने से प्रतिस्पर्धात्मक विपणन भी बढ़ा।

तालिका 2: वर्ष 2010 में MSP और बाजार मूल्य की तुलना (रु./क्विंटल)

वर्ष	MSP (रु./क्विंटल)	बाजार मूल्य (रु./क्विंटल)
2007	850	800
2008	900	850
2009	950	920
2010	1000	970

तालिका से स्पष्ट है कि MSP बाजार मूल्य से अधिक था, जिससे किसानों को लाभ हुआ, लेकिन बाज़ार मूल्य MSP के काफी करीब था, जिससे सरकार को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण की आवश्यकता थी।

वर्ष 2010 में किसानों को भुगतान में होने वाली औसत देरी

तालिका 3 के आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण दर्शाता है कि वर्ष 2007 से 2010 के बीच किसानों को धान बेचने के बाद भुगतान प्राप्त करने में होने वाली औसत देरी में लगातार कमी आई। वर्ष 2007 में किसानों को औसतन 20 दिनों तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन वर्ष 2008 में यह देरी घटकर 18 दिन रह गई, जो 10% की कमी को दर्शाती है। इसी प्रवृत्ति को देखते हुए, वर्ष 2009 में औसत भुगतान देरी और कम होकर 15 दिन रह गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.67% की कमी को दर्शाती है। वर्ष 2010 में यह देरी घटकर 12 दिन रह गई, जो चार वर्षों में कुल 40% की गिरावट को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि सरकार और सहकारी विपणन संघ ने भुगतान प्रक्रिया को तेज़ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधार किए, जिससे किसानों को समय पर धनराशि प्राप्त हो सके और उनकी आर्थिक स्थिरता बढ़े।

तालिका 3: वर्ष 2010 में किसानों को भुगतान में होने वाली औसत देरी (दिनों में)

वर्ष	औसत भुगतान देरी (दिनों में)
2007	20
2008	18
2009	15
2010	12

इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने भुगतान प्रक्रिया में सुधार किया, लेकिन किसानों को अब भी औसतन 12 दिनों तक भुगतान के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी।

वर्ष 2010 में भंडारण सुविधाओं की क्षमता

तालिका 4 के आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण दर्शाता है कि वर्ष 2007 से 2010 के बीच रायपुर जिले में धान के भंडारण की क्षमता में लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2007 में भंडारण क्षमता 1,50,000 मेट्रिक टन थी, जो वर्ष 2008 में बढ़कर 1,70,000 मेट्रिक टन हो गई, यानी 13.33% की वृद्धि हुई। इसी तरह, वर्ष 2009 में यह क्षमता 1,90,000 मेट्रिक टन तक पहुँच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.76% अधिक थी। वर्ष 2010 में भंडारण क्षमता बढ़कर 2,10,000 मेट्रिक टन हो गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चार वर्षों में कुल 40% की वृद्धि दर्ज की गई। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि धान उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ भंडारण सुविधाओं का विस्तार भी किया गया, ताकि खरीदी गई उपज को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके। सहकारी विपणन संघ और सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों ने किसानों को उनकी उपज के सुरक्षित भंडारण का लाभ प्रदान किया।

तालिका 4: वर्ष 2010 में भंडारण सुविधाओं की क्षमता (मेट्रिक टन में)

वर्ष	भंडारण क्षमता
2007	1,50,000
2008	1,70,000
2009	1,90,000
2010	2,10,000

सरकार द्वारा भंडारण क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए गए, लेकिन यह अब भी मांग की तुलना में अपर्याप्त थी।

5. निष्कर्ष

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ ने धान खरीदी और भंडारण प्रक्रिया को सुचारू और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धान खरीदी केंद्रों की संख्या वर्ष 2007 से 2010 तक 300 से बढ़कर 450 हो गई, जिससे अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ मिल सका। MSP में भी निरंतर वृद्धि हुई, और बाजार मूल्य इसके निकट आते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बनता गया। इससे सरकारी हस्तक्षेप की प्रासंगिकता बनी रही, लेकिन साथ ही बाज़ार मूल्य निर्धारण की नई रणनीतियों की आवश्यकता भी महसूस की गई। किसानों को भुगतान मिलने में देरी वर्ष 2007 में औसतन 20 दिन थी, जो 2010 तक घटकर 12 दिन रह गई, जिससे भुगतान प्रक्रिया में सुधार का संकेत मिलता है। भंडारण क्षमता भी लगातार बढ़ी और वर्ष 2007 में 1,50,000 मेट्रिक टन से बढ़कर 2010 में 2,10,000 मेट्रिक टन हो

गई, जिससे खरीदे गए धान का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित हुआ। यह अध्ययन दर्शाता है कि सहकारी विपणन संघ की नीतियों ने किसानों को बाजार अस्थिरता से बचाने में मदद की। हालांकि, भविष्य में भुगतान प्रक्रिया को और तेज़ करने, भंडारण सुविधाओं के विस्तार, और बाजार मूल्य स्थिरता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी।

भविष्य की संभावनाएँ

1. त्वरित भुगतान प्रणाली - डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर किसानों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जा सकता है।
2. भंडारण सुविधाओं का विस्तार - आधुनिक साइलो स्टोरेज और जलवायु-नियंत्रित वेयरहाउस से भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है।
3. MSP और बाजार मूल्य स्थिरता - मूल्य निर्धारण सुधार और ऑनलाइन ट्रेडिंग से किसानों को अधिक लाभकारी मूल्य मिल सकता है।
4. किसानों का प्रशिक्षण और जागरूकता - विपणन प्रणाली और आधुनिक कृषि तकनीकों पर प्रशिक्षण से उनकी आय और उत्पादकता बढ़ेगी।

संदर्भ

1. मिश्रा, सी. एस. (1986). बस्तर जिले में धान के समर्थन मूल्य की समस्या (अप्रकाशित रिपोर्ट), पृष्ठ 118।
2. अनाम. (2007). नाबार्ड राइस मिल्स इन इंडिया। प्राप्त किया गया www.Nabard.org से।
3. गोयल, आर. सी., & गंगवार, ए. सी. (1983). हरियाणा में धान प्रसंस्करण का एक आर्थिक विश्लेषण। *भारतीय कृषि परिदृश्य*, 195-198।
4. गुप्ता, एस. के., अरोड़ा, साधना, & सहगल, वी. के. (2000). पंजाब में आधुनिक चावल मिलिंग प्रणाली का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन। *पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान पत्रिका*, 37(3-4), 232-238।
5. राजगोपाल. (1988). आधुनिक सहकारी चावल मिलों की अर्थव्यवस्था: एक अध्ययन। *भारतीय सहकारी समीक्षा*, 26(1), 34-41।
6. फाल्कनर, जे. (1993). दक्षिणी घाना में गैर-काष्ठ वन उत्पाद: मुख्य रिपोर्ट। यू.के.: नेचुरल रिसोर्स इंस्टीट्यूट।

7. हासालकर, एस., & जाधव, वी. (2004). गैर-काष्ठ वन उत्पादों के उपयोग में महिलाओं की भूमिका। *सामाजिक विज्ञान पत्रिका*, 8(3), 203-206।
8. खरे, ए. (1998). भारत में सामुदायिक आधारित संरक्षण। *सामुदायिक एवं संरक्षण* में। नई दिल्ली: पेज पब्लिकेशन।
9. मराठिया, डी. के., & गौड़हा, ए. के. (1992). जनजातीय अर्थव्यवस्था में विसंवैधानिक एमएफपी का विपणन। *भारतीय कृषि विपणन पत्रिका*, 6(2), 54-91।
10. प्रसाद, बी. एन. (1994). क्षेत्रीय गैर-काष्ठ वन उत्पाद उद्योग। कुआलालंपुर: उद्योग विकास समूह, एशिया-प्रशांत क्षेत्र, एफएओ।
11. राव, आई. एम. के. (1988). जनजातीय अर्थव्यवस्था में विपणन। नई दिल्ली: इंटर इंडिया पब्लिकेशन।
12. सक्सेना, एन. सी. (1975). जन, लाभ और वन। नई दिल्ली: नटराज पब्लिशर्स।
13. तिवारी, एस. (2000). बस्तर का इमली आंदोलन। रायपुर: स्मृति प्रिंटर।

IJMRR